

# 39 'आदिवासियों' को महाराष्ट्र पुलिस ने कथित मुठभेड़ में मार गिराया, गढ़चिरौली की अंतर्विरोधी दास्तान

अंजनी कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता

माओवादियों के हथियार लड़ाई में चूक गये तब क्या एक भी पुलिस वाला घायल नहीं हुआ? यदि वे चारों तरफ से घिरे थे और कैप लगाये थे तो उनके सामान कहाँ गये, उनके किट आदि कहाँ हैं...

पिछले दो दिनों से गढ़चिरौली से माओवादियों के मारे जाने की खबर आ रही थी। एक के बाद दूसरे 'एनकाउंटर' में अब तक कुल 39 माओवादियों के मारे जाने की खबर भी सनसनीखेज नहीं बन सकी है।

इस कथित मुठभेड़ में पुलिस बल के एक भी सदस्य के घायल की खबर नहीं आई है। पुलिस डीआईजी देशमुख की मानें तो %हमारे आदमियों ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था। उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। कुछ इसी कारण से इंद्रावती नदी में कूद गये। उनमें से कई शायद घायल होने के कारण तैर नहीं सके और डूब गये। इस नदी में घड़ियाल भी हैं जिन्होंने उन पर हमला भी किया होगा। जो बच गये वे हमारी गोलियों का शिकार हो गये।

यह एक पुलिस प्रमुख द्वारा मुठभेड़ का साहित्यिक विवरण है। इंडियन एक्सप्रेस की उपरोक्त रिपोर्ट में कुछ और अंशों का पढ़ा जाना चाहिए। पुलिस ने एक भेदिये के माध्यम से यह खबर हासिल की थी कि सीपीआई-माओवादी के दलम के लोग कैप लगाने वाले हैं। यह खबर पुलिस को पकड़े तौर पर हासिल थी इसीलिए उन्होंने दो किलोमीटर के दायरे में घेराबंदी की, जिससे कि माओवादी भाग न सकें।

घेराबंदी के बाद उन पर 12-13 ग्रेनेड फेंके गये और 2000 राउंड गोलियाँ चलाई गई। इस तरह माओवादी पूरी तरह से घिरे हुए मारे गये। हालांकि पुलिस का मानना है कि कुछ बचकर निकल गये हैं और गांव, बाजार और डॉक्टरों के डिस्पेंसरी पर नजर रखी जा रही है जिससे कि उन्हें भी खत्म किया जा सके।

पुलिस प्रमुख का कहना है कि 'उनके भाग सकने का कोई अवसर ही नहीं था।' और 'उनके हथियार पूरी तरह खत्म हो चुके थे।' पुलिस को माओवादियों से एक इंसास राईफल्स, एक .303, एक कार्बाइन, दो 8 एमएम की बंदूक, एक बारह बोर की बंदूक नदी के किनारे से मिली है।' पुलिस के अनुसार एक दलम में लगभग 20 से 22 सदस्य होते हैं। पुलिस को खबर थी कि कैप लगाने के लिए दो दलम के लोग आ रहे हैं। यानी कुल 40 से 44 माओवादी इकट्ठा हैं। 'टोस खबर' के आधार पर सी-60 की दो कंपनी ने 37



माओवादियों को मार डाला गया जिसमें 6 पास में ही अन्य मुठभेड़ में मारे गये।

पुलिस की कहानी से जिन बातों का उत्तर नहीं मिलता -

1- यदि यह दलम का कैप था तो उनके हथियार कहाँ गये? क्या दलम के सदस्य खाली हाथ थे? या वे दलम के सदस्य नहीं थे? यदि दलम के सदस्य हथियारबंद थे और कैप लगा रहे थे तो निश्चय ही गुरिल्ला ट्रेनिंग उसका हिस्सा होगा? यदि वे सांस्कृतिक कर्मी थे तब क्या वे पुलिस के साथ इतनी लंबी मुठभेड़ में लगे रहे?

2- माओवादियों के हथियार लड़ाई में चूक गये तब क्या एक भी पुलिस वाला घायल नहीं हुआ? यदि वे चारों तरफ से घिरे थे और कैप लगाये थे तो उनके सामान कहाँ गये, उनके किट आदि कहाँ हैं?

3- पुलिस को जो 'टोस खबर' थी उससे दो किमी के दायरे में घेराबंदी की गई। नदी के हिस्से को छोड़कर पीछे से घेराबंदी का दायरा दो किमी रखने पर सी-60 की दो कंपनियों घेराबंदी के लिए पर्याप्त थीं?

इस सवाल को पुलिस की कहानी के संदर्भ में रखें तो और भी साफ होता है जब बारिश के कारण माओवादियों की लाशों वे दूढ़ नहीं पा रहे हैं और अन्य गतिविधियाँ चलाने में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि यह इलाका कच्चा, जंगल से भरा और कठिन है।

और, दूसरी बात यह भी है कि माओवादी जिस गुरिल्ला रणनीति का पालन करते हैं,

उसका ट्रेन कठिन और जटिल होता है। ऐसे में 'टोस खबर' पर 'घेराबंदी' और आत्मसमर्पण की अपील के बाद माओवादियों को 'मार गिराने' की बातों में कई अंतर्विरोध दिखते हैं जिस पर पत्रकारों की ओर से अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है।

जो रिपोर्ट आई है वह उन्हें दी गई खबरों का ही अखबारी तर्जुमा जैसा दिखता है। ग्राउंड रिपोर्ट की उम्मीद है जिसे निश्चय ही पत्रकार अंजाम देंगे। लेकिन उससे भी अधिक मुख्य बात यह 'मुठभेड़' है। इस मुठभेड़ को एक जीत की तरह पेश किया गया है।

एक दूसरी तरह की मुठभेड़ से उत्तर प्रदेश भी गुजर रहा है, जहाँ पुलिस और मुख्यमंत्री 'न्याय' की कुर्सी पर बैठे हैं और जीवन और मौत को तय कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से पुलिस, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, कॉरपोरेट घराने, विदेशी हथियारों के दलाल और गुप्तचर, मीडिया के घराने और पार्टियों के नेता, निजी हथियारबंद गिरोह, जातीय गिरोह आदि नक्सलवाद को खत्म करने में लगे हुए हैं।

चलिए गढ़चिरौली में हुई 'मुठभेड़' एक बहुत बड़े समूह का नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध है। यह अपने ही देश की जनता के

खिलाफ युद्ध है और इस युद्ध में युद्ध की संयुक्त राष्ट्र की न्यूनतम दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर सारे तरीके अख्तियार किये जा रहे हैं। गढ़चिरौली में 'मुठभेड़' की कहानी भी यही है। यही कारण है तीन राज्यों की सरकारें पुलिस को करोड़ों रुपये इनाम दे रही हैं।

क्या यह सचमुच बहादुरी है? देश की सीमा पर लड़ जाने वाला युद्ध है? यदि यह युद्ध नहीं है तब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इनाम देने के बजाय मुठभेड़ में शामिल लोगों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, इसकी स्वतंत्र जांच होना चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है? इशरत जहाँ आदि के मुठभेड़ के मामले पर न्यायपालिका में उठे संकट को हम देख रहे हैं।

मुठभेड़ के इसी दौर में नक्सलवाद खत्म करने के लिए सेना के हथियारों से लैस सीमा सुरक्षा बल और अन्य पुलिस बलों द्वारा कोलहान में लगातार मोर्चा आदि से हमला किया जा रहा है और घेराबंदी कर रसद को रोक दिया गया है। यहाँ फिलहाल मुठभेड़ नहीं घेरकर माओवादियों को मारने की नीति का पालन किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही किसी माओवादी की लाश मिली वैसे ही इसे

'मुठभेड़' में मार गिराने की खबर छप जायेगी।

युद्ध और मुठभेड़ के बीच का फर्क सिर्फ अखबारों की खबरों में तकनीकी पक्ष तक सीमित रह गया है। इस सच्चाई को ठीक से पढ़ने के लिए जरूरी है कि फर्क को हटाकर पढ़ा जाये।

मसलन, यूएपीए के प्रावधानों और देशद्रोह की धाराओं में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धारा को मुख्य माना गया है। लेकिन यहाँ 'मुठभेड़' को किस धारा में पढ़ा जाय? माननीय न्यायालयों ने तो इस 'मुठभेड़' पर अपनी राय और निर्देश दिये हैं, लेकिन क्या यह लागू हो पा रहा है? निश्चय ही मानवाधिकार कार्यकर्ता ही नहीं देश के सभी प्रबुद्ध समाज के लोगों को बहस-मुहाबिसे के माध्यम से मसले को उठाना चाहिए।

बहुत सारे लोग यह सवाल उठायेगे और उठाते ही हैं कि माओवादी भी पुलिस को मारते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और, इस बात को जरूर जानना चाहिए कि यह सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? जब नक्सली नहीं थे तब भी पुलिस थी; तब भी पुलिस और सेना-अर्धसेना ऐसे ही मुठभेड़ों में लोगों को मार गिराती थी और कई बार दूसरे पक्ष लोग भी ऐसा करते थे। मरने वालों की संख्या हजारों में होती थी।

उसके पहले ब्रिटिश सरकार और उसकी पुलिस, सेना थी, लोगों को मुठभेड़ में मार डालने का काम वह भी खूब क्रूरता के साथ करते थे। सिलसिले को आगे करें या पीछे मुठभेड़ की कहानियाँ और मातें आपको दिखाई देंगी।

सत्ता रूप बदलते हुए हमारे सामने आज जिस रूप में दिख रहा है, उसमें यह सवाल उठाना जरूरी है कि मौतों का यह सिलसिला क्यों जारी है? हिंसा क्यों जारी है? हिंसा सत्ता में है या उन लोगों में जो जनता के बीच से उठते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं।

एक तुलनात्मक अध्ययन से यह बात साफ हो सकती है, यदि हम देश में साल भर में हिंसा का रास्ता अपनाने वाले सारे समूहों, संस्थानों, पार्टियों, संगठनों आदि जिसमें पुलिस के विविध रूप भी हैं, के द्वारा की गई हिंसक कार्यवाहियों का अध्ययन करें और यह न मानें कि पुलिस आदि शांति के दूत के रूप में काम करती हैं।

## गाली खाओ सेहतमंद रहो, मोई जी पिछले दो दशक से रोज़ाना किलो दो किलो गाली खा रहे हैं!

गिरीश चंद्र मालवीय

पुण्यभूमि आर्यावर्त का ही प्रताप है कि इसमें मोई जी सरीखे कर्मठ और विचारशील प्राणी का जन्म हुआ है।

लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में 'भारत की बात सबके साथ' कार्यक्रम में मोई जी ने जो सूत्र हमें दिया है उसकी तो मिसाल किसी संत किसी प्रवचनकार ने भी नहीं सोची होगी। ध्यान दिजिएगा उन्होंने कहा, 'मैं करीब दो दशकों से लगातार वन के.जी. (एक किलो), टू के.जी. (दो किलो) गालियाँ खाता हूँ।

यह अकल्पनीय सूत्र था। हमें लगता है कि जैसे महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के कल्याण के लिये 'अप्य दीपो भव' का सूत्र दिया था उसी प्रकार भगवान कल्कि के अवतार के रूप में जन्म लेकर मोईजी ने यह निराला सूत्र दिया 'गाली खाओ स्वस्थ रहो'। हम बचपन में स्वेट मॉर्डन के सफलता के सूत्र पढ़ते थे पर अब लगता है कि स्वेट मॉर्डन भी मोई जी के पाँव धो धो कर पियेगा कि गुरु..... कहाँ से लाते हो....।

यह निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए की भी अगली स्टेप है रोज एक दो किलो गाली खाओ ओर स्वास्थ्य लाभ लो, लेकिन हमें इस निराले सूत्र में उस महान कवि का योगदान नहीं भुलाना चाहिए

जिसने यह प्रश्न पूछा ?

'प्रधानमंत्री जी आप हम सभी भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटे काम करना छोटी बात नहीं है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है' ?

जितना जवाब अद्भुत था उतना ही यह प्रश्न भी मारक था 'इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं ?...।

इन्ही के लिए कहा गया है 'जहां न पुहंचे रवि वहाँ पुहंचे कवि'। प्राचीन समय में एक कालिदास हुए हैं जो जिस डाल पर बैठे उसी को काटने लगे और आज यह मॉडर्न कालिदास के रूप में प्रसून जोशी जी हैं जो ऐसा प्रश्न पूछते हैं.....

क्या आप सूरज से पूछोगे कि इतना ताप इतना प्रकाश वह कहाँ से लाता है ?...

क्या आप चन्द्रमा से पूछते हैं कि इतनी शीतलता वह कहाँ से लाता है ?...

अरे...मोई जी जैसे अखंड ऊर्जा के स्रोत से आप ऊर्जा का उदगम पूछ रहे हो ? मोई जी तो यूरेनियम का भंडार हैं। पूरी पृथ्वी में जितना यूरेनियम मौजूद होगा उतना तो अकेला मोई जी में मौजूद है। उनसे तो उनकी ऊर्जा की बात करना समन्दर में से अंजुली भर जल लेने की बात करना है।

लेकिन वह सिर्फ अखंड ऊर्जा के स्रोत नहीं है वह करुणा निधान भी हैं। कभी कभी वह मंच पर भाषण करते करते इतने द्रवित हो जाते हैं कि चौराहे पर लगे खम्बे भी बोलने लग जाते हैं कि... हे दया निधान हमारा उध्दार करने कब पधार रहे हो ? प्राचीन काल में शिला बनी। अहिल्या का उध्दार राम ने किया था हम म्युनिस्पैलिटी के खम्बो का उध्दार कब करोगे प्रभु... !!!!

नरोत्तमदास ने कहा है 'देखि सुदामा की दीन दसा, करुना करिके करुनानिधि रोये'। इतनी ही करुणा मोई जी में भी है। कुत्ते के पिछले के गाड़ी में नीचे आ जाने की कल्पना मात्र से वह द्रवित हो जाते हैं। उन्होंने अपने मुखारविंद से यह सुमधुर वचन निकाले हैं...

'अगर कुत्ते का पिछला भी आपकी गाड़ी के नीचे आ जाए तो आपको दुख होता है कि नहीं'। इतनी करुणा देख कर तो करुनानिधि भी रो पड़ते हैं ( तमिलनाडु वाले नहीं स्वयं विष्णु भगवान )

उनके ऐसे आस वचन सुन सुन कर हमें जिस शांति का अनुभव होता है वह अनिर्वचनीय है।

हमें तो लगता है कि उनके नाम की मोई चालीसा हर भारत वासी को जपना चाहिए। हो सकता है इससे क्रूड ऑयल के ही दाम कम हो जाए।

## मोदी सरकार की नोटबन्दी ओर बिना तैयारी की जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी

यह भारत के व्यापारियों उद्योगपतियों की सबसे प्रतिष्ठित संस्था पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कह रही है..... इस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है 'कारोबार, उद्योग एवं निर्यातकों पर जीएसटी का असर'। रिपोर्ट को जारी करते हुए संगठन के अध्यक्ष अनिल खेतान ने कहा कि नोटबन्दी के असर तथा जीएसटी की रुकावटों जैसे विभिन्न संरचनात्मक एवं घरेलू कारकों से निर्यात वृद्धि पर बुरा असर पड़ा है।

कई निर्यातक अभी भी एकिकृत जीएसटी के अपने बकाया रिफंड के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इससे उनको दैनिक खर्च की पूंजी का अभाव है और वे काम नहीं कर पा रहे हैं।

पीएचडी चैंबर मानता है कि देश के निर्यात पर बहुत खराब असर पड़ा है। जीएसटी के बकायों की वापसी में देरी और नोटबन्दी के प्रभाव जैसी रुकावटों की वजह से अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे मुख्य बाजारों समेत वैश्विक मांग में सुधार के बाद भी 2017-18 में देश का निर्यात प्रभावित होकर उम्मीद से कम रहा जबकि इस साल अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे मुख्य बाजारों के आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

छोटे छोटे देशों का निर्यात इस दौरान बढ़ा है। इस दौरान दक्षिण कोरिया का निर्यात 16 प्रतिशत, इंडोनेशिया का 17 प्रतिशत और मलेशिया का 15 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन हम कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए।

उन्होंने कहा कि 2017-18 को भारत के लिए निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि से चूकने के लिए याद किया जाएगा, पिछले वित्त वर्ष में व्यापार घाटा एक साल पहले के 108 अरब डॉलर से 45 प्रतिशत बढ़कर 157 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।

क्या व्यापार घाटा बढ़ने में भी नेहरू की गलती बता दी जाएगी.....